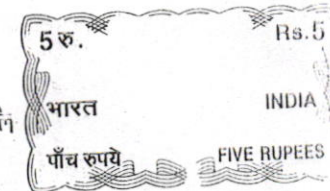
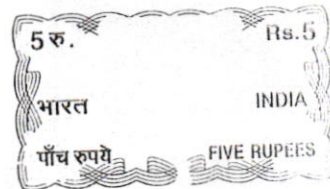


116



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालि
प्र. क्र. रिग/3910-II-15

1- श्रीमान श्री 1644 श्री अरुण
1.3. समर वहादुर सिंह 2 अमर वहादुर सिंह

3. दशरथ सिंह 4. पद्मनाथ सभी पुत्रगण
संतकुमार, उम्र क्रमशः 56, 48, 45, 42
दांदा सभी खेती निवासीगण ग्राम
करोँदिया दक्षिण तोला सीधी तह.
गोपदवनास जिला सीधी म.प्र.

-- अपीलान्ट --- श्री अरुण
बनाम

1. गिरेन्द्र वहादुर सिंह पुत्र भिम्मा सिंह
चौहान उम्र 65 वर्ष दांदा छोती
निवासी ग्राम करोँदिया दक्षिण तोला
तहसाल गोपदवनास जिला सीधी म.प्र.

2. म.प्र. शासन --- 00000000
रिस्पण्डेंस

सेकण्ड अपील 00000000 अन्तर्गत धारा 44 50 के, नये संशोधन आंदा. 2011
म.प्र. भू. रा. स. 1959 विद्व आदेशा दिनांक 3.10.15 द्वारा
पारित न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग प्र. क्र. 8/अपील
15-16 के निणयि ले दुहानि होकर ।

श्रीमान जी,

अपीलान्ट की अपील तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, ग्राम करोँदिया दक्षिण तोला तह. गोपदवनास सर्वे न.
301 रकबा 0.59 के भूमि स्वामी एवं आधापत्यधारो रेषो.
प्र. 1 है व काल से लगा हुआ सर्वे न. 300 के भूमि स्वामी एवं

दिनांक 2-12-15 का
श्री रामसेवक शर्मा, कागि
डाटा प्रस्तुत
2-12-15
50

(मनेक शर्मा कागि)
डाटा प्रस्तुत
2-12-15

M

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3910-दो/2015

जिला सीधी

गोपाल सिंह आदि

विरुद्ध

गिरेन्द्र बहादुर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२३-९-२०१६	<p>आवेदक अधिवक्ता ने अपर आयुक्त, के प्रकरण क्रमांक ८/अपील/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक ३-१०-१५ के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनोदक क्रमांक १ गिरेन्द्र बहादुर सिंह ने एक आवेदन म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा १०७(५) के तहत उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि सर्वे क्रमांक ३०१ रकबा ०.२५९ हैक्टर के भूमिस्वामी गिरेन्द्र सिंह है। उक्त सर्वे नम्बर में नये नक्शे तथा पुराने नक्शे से मिलान नहीं हो रहा है। इस कारण नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा मौजा पटवारी व राजस्व निरीक्षक को सर्वे नं ३०१ रकबा ०.२५९ हेक्टेयर के सम्बन्ध में स्थल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दौरान कार्यवाही आवेदकगण द्वारा प्रकरण में जानकारी होने पर आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो आवेदकगणों को पक्षकार बनाया और न आपत्ति पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा आपत्ति निरस्त कर दी तथा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट व मौजा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नक्शा दुरुस्ती हेतु कलेक्टर सीधी की ओर भेजा। अपर कलेक्टर सीधी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २९/अ-७४/१४-१५ पर दर्ज कर आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर न देते हुये दिनांक ४-७-१५ को नक्शा दुरुस्ती के आदेश दिये। इसके विरुद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक ८/अपील/१५-१६ पर दर्ज किया तथा आदेश दिनांक</p>	

M

3-10-15 को अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कायम कर अग्रिम कार्यवाही की गई है, जबकि संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में अनुविभागीय अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बापस करना चाहिए था। इसके बावजूद भी अनुविभागीय ने प्रकरण कायम करने में अवैधानिकता की गई है। यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अपर कलेक्टर को अग्रेषित किया है, परन्तु उसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी थी, जिनकर पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को था। उक्त अग्रेषित प्रकरण के तारतम्य में अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा दुरुस्ती के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। आवेदकगण को प्रकरण में पूर्ण सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है तथा इन कानूनी बिन्दुओं को अनदेखा कर अपर आयुक्त द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया है। इस कारण अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दि० 4-7-15 व अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 3-10-15 अवैध एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि क्रमांक 301 रकवा 0.259 हेक्टर का नक्शा जिसके द्वारा कब त्रुटिपूर्ण नक्शा बनाया गया वह तथ्य अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में नहीं बताया है। अपने तर्कों के समर्थन में एम०पी०एल०जे० 2004(1) एस०एन० 1

✓

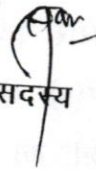
3

शिवनाथप्रसाद श्रीवास्तव तथा अन्य विरुद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य व आरएन 2002 पेज 238 एवं आरएन 2005 पेज 240 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि नक्शा दुरुस्ती कार्यवाही अपर कलेक्टर सीधी द्वारा की गई है जो उचित एवं वैधानिक है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 4-7-15 के द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र नक्शा दुरुस्ती हेतु संहिता की धारा 107(5) के तहत आवेदन पत्र उपखण्डीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक व मौजा पटवारी से नक्शा त्रुटि सुधार हेतु स्थल जॉच व पंचनामा प्राप्त कर प्रकरण नक्शा दुरुस्ती हेतु कलेक्टर सीधी को भेजा है तथा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई व राजस्व निरीक्षक व मौजा पटवारी की रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण का अवसर न देकर पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) के तहत खेत का नक्शा दुरुस्त करने या पुनरीक्षित करने का अधिकार कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी को है। अधीनस्थ न्यायालय नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही नहीं कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में गिरेन्द्र सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष नक्शा दुरुस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया था तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही की गई है, वह क्षेत्राधिकार रहित है और उचित व वैधानिक नहीं है। अनावेदक द्वारा नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में

त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बापस करना चाहिए था। इसके बावजूद भी अनुविभागीय ने प्रकरण कायम करने में अवैधानिकता की गई है। यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अपर कलेक्टर को अग्रेषित किया है, परन्तु उसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी थी, जिनकर पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को था। उक्त अग्रेषित प्रकरण के तारतम्य में अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा दुरुस्ती के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। इस कानूनी बिन्दु का अपर आयुक्त द्वारा अनदेखी कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुये निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक 29/अ-74/14-15 आदेश दिनांक 4-7-15 व अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण क्रमांक 08/अपील/15-16 आदेश दिनांक 03-10-15 अनियमित व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में विवादित सर्वे नं. 301 के नक्शे में आदेश दिनांक 04-7-15 के पूर्व की स्थिति की कायम करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


सदस्य

